भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3535
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का कार्यान्वयन

3535. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को कार्यान्वित करने वाले विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनके नाम क्या हैं;
(ख) क्या उक्त नीति के अंतर्गत कोई कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को माध्यम के रूप में अपनाने की पहल को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। एनईपी 2020 में कार्यान्वयन के लिए विभिन्न समय-सीमाएं, सिद्धांत और कार्यप्रणाली हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य समान रूप से उत्तरदायी हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के नियामक और कार्यान्वयन निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहलें की हैं।

(ख): एनईपी 2020 में व्यावसायिक और व्यावहारिक कौशल को स्कूल और उच्चतर शिक्षा में शामिल करके मुख्यधारा की शिक्षा के साथ कौशल विकास को एकीकृत करने पर बल दिया गया है, जिससे व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के बीच के भारी अंतर को दूर किया जा सके। एनईपी में मिडिल और माध्यमिक विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर पर व्यवसायपरक शिक्षा उपलब्ध कराने का भी आह्वान किया गया है।

एनईपी 2020 के अनुसरण में और केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के कौशल शिक्षा घटक के तहत, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ़) के अनुरूप कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा IX और X में, छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में कौशल मॉड्यूल प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, अर्थात् कक्षा XI और XII में, कौशल पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (इलेक्टिव) विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। समग्र शिक्षा के नवाचार घटक के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव, 10 बस्ता रहित दिवस आदि को शामिल किया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, एनएसक्यूएफ स्तर के अनुरूप जॉब रोल्स (जेआर) को नए युग के कौशलों जैसे उद्योग 4.0, वेब 3.0, एआई/एमएल, एआर/वीआर, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थव्यवस्था और एनर्जी ट्रांजीशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यान्वित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को एक व्यापक क्रेडिट फ्रेमवर्क के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें प्रारंभिक, स्कूल, उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को शामिल किया गया है, जो विभिन्न आयामों अर्थात शैक्षणिक, व्यवसायपरक कौशल और अनुभवात्मक अधिगम, जिसमें प्रासंगिक अनुभव और दक्षता/पेशेवर स्तर प्राप्ति शामिल है, के क्रेडिटीकरण को एकीकृत करता है। एनसीआरएफ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है और यह मूल्यांकन के अध्यधीन सभी प्रकार के अधिगम व असाइनमेंट के क्रेडिटीकरण तथा क्रेडिट्स के संचयन, भंडारण, अंतरण और पुन: उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, यह व्यवसायपरक और सामान्य शिक्षा के बीच भेद को समाप्त करता है तथा उनके बीच अकादमिक समतुल्यता स्थापित करते हुए शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के बीच गतिशीलता को संभव बनाता है।

(ग): एनईपी 2020 की घोषणा के बाद स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। स्कूली शिक्षा में स्कूलों के स्तरोन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया); सभी बच्चों के लिए समावेशी और समतापूर्ण कक्षा परिवेश के साथ गुणवत्तापूर्ण

शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा; कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ के साथ पढ़ने और संख्या ज्ञान में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत); विद्या-प्रवेश-तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश; शिक्षा के लिए सुसंगत बहु-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या, ई-बुक्स और ई-कंटेंट वाले वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर), 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल-आधारित शिक्षण सामग्री के लिए मूलभूत स्तर हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) और जादुई पिटारा का शुभारंभ; परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण); निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) 1.0, 2.0 और 3.0; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर), 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी गैर-साक्षरों को लक्षित करते हुए "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास" योजना का कार्यान्वयन, आदि जैसी कई पहले की गई हैं।

उच्चतर शिक्षा में, अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसे दिशानिर्देशों/विनियमों के साथ राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ); उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रम में बहु प्रवेश और निकास; उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को बहु-विषयक संस्थाओं में परिवर्तित करना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम करना; प्रत्येक छात्र की स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत के साथ एक सरल, पारदर्शी व विद्यार्थी-अनुकूल और पूर्णत: डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण को सक्षम बनाना; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति; विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित मौजूदा जनशक्ति का कौशलोन्नयन और पुनः कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से नए स्वयम प्लस पोर्टल का शुभारंभ; समर्थ के माध्यम से प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस संबंधी दिशानिर्देश; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विदेश से छात्रों को प्रवेश देने हेतु अतिरिक्त सीटों

के लिए दिशानिर्देश; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय एचईआई की बढ़ती प्रतिष्ठा; शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना आदि जैसी विभिन्न पहल/सुधार किए गए हैं।
एनईपी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करने और नवीन विचारों पर चर्चा करने के लिए, समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थाओं, अन्य हितधारकों के साथ कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।

(घ): एनईपी 2020 बहुभाषावाद को बढ़ावा देने पर बल देती है और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। यह सभी भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन पर केंद्रित है, तथा जहां तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक, तथा अधिमानतः कक्षा 8 तक, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा के उपयोग की सिफारिश करती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पूरे भारत में प्रारंभिक साक्षरता और बहुभाषी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 22 अनुसूचित और 99 गैर-अनुसूचित भाषाओं में 117 प्राइमरों के विकास के साथ-साथ एनसीईआरटी और सीआईआईएल द्वारा स्थानीय और मातृभाषाओं में 52 अतिरिक्त प्राइमरों का विकास जैसी कई प्रमुख पहलों को लागू किया है। भाषा संगम (जिसमें 22 भाषाओं में 100 सामान्यतः प्रचलित वाक्य शामिल हैं), भारतीय भाषा उत्सव, और भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर (भाषा और सांस्कृतिक शिक्षा पर केंद्रित 28 घंटे का एक विकल्प आधारित कार्यक्रम) जैसी पहलों ने छात्रों में भाषाई और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय पहचान को दर्शाने के लिए कक्षा 6 से 9 तक के लिए भाषा और संस्कृति की 16 पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं।

जादुई पिटारा और इसके एआई-सक्षम डिजिटल संस्करण, ई-जादुई पिटारा जैसे नवीन उपकरणों ने भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) की सहायता से साथ 22 भारतीय भाषाओं में समावेशी, खेल-आधारित प्रारंभिक शिक्षा शुरू की है। दीक्षा प्लेटफॉर्म अब 36 भाषाओं में बहुभाषी डिजिटल सामग्री प्रदान करता है। "एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म" की संकल्पना के साथ, पीएम ई-विद्या पहल का विस्तार 200 डीटीएच टीवी चैनलों तक हो गया है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईएसएल में पाठ्यचर्या के अनुरूप सामग्री प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच और समावेशिता बढ़ती है। शिक्षक शिक्षा में भी विशेष रूप से बहुभाषी शिक्षाशास्त्र पर केंद्रित 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) की शुरुआत के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

बजट 2025-26 में, सरकार ने स्कूलों और उच्चतर शिक्षा के लिए प्रदान किए जा रहे विषयों के लिए पाठ्यपुस्तकों और अध्ययन सामग्री के अनुवाद के लिए भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना की घोषणा की है, जिसे डिजिटल रूप में 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

******